नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 211
दि. 05.05.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

- बिहार की जीत के बाद ही मोदी ने कहा था बिहार से ही बंगाल पहुंचती है गंगा
- शाह ने दिया था अंग,बंग व कलिंग का नारा, पूरे समय संभाले रहे कमान
- भूपेंद्र यादव बने भाजपा के सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार

गंगोत्री से गंगासागर तक: पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और राजनीतिक भूचाल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति ने 4 मई 2026 की शाम एक ऐसा मोड़ देखा, जिसने राज्य के राजनीतिक इतिहास को नई दिशा दे दी। दशकों से चली आ रही सत्ता संरचना अचानक बदल गई और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बहुमत हासिल कर राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह भगवा रंग में रंग दिया। इस परिवर्तन को राजनीतिक विश्लेषक एक साधारण चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि एक लंबी रणनीतिक यात्रा का परिणाम मान रहे हैं, जिसे कई लोग "राजनीतिक भागीरथी" की संज्ञा दे रहे हैं—जो गंगोत्री से गंगासागर तक पहुंचती दिखाई दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटों में से भाजपा ने 208 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 79 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस केवल दो सीटों तक सिमट गई। यह परिणाम राज्य की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है, जहां वर्षों से स्थापित सत्ता समीकरण अचानक बदल गए। इस चुनावी बदलाव को कई राजनीतिक घटनाओं और रणनीतिक फैसलों से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दिया था कि "बिहार से बंगाल तक गंगा का प्रवाह राजनीतिक रूप से भी पहुंचता है," जो अब एक प्रतीकात्मक रूप में साकार होता दिख रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे चुनावी अभियान के दौरान "अंग, बंग और कलिंग" का नारा देते हुए संगठनात्मक स्तर पर व्यापक रणनीति को आगे बढ़ाया।

इस ऐतिहासिक जीत के पीछे भाजपा के संगठनात्मक ढांचे और रणनीतिक योजना का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है। पार्टी के चुनावी प्रबंधन में भूपेंद्र यादव की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिन्हें राजनीतिक विश्लेषक पार्टी का सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार मान रहे हैं। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया और विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय एजेंडे से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस चुनाव ने कई बड़े राजनीतिक चेहरों के भविष्य पर भी असर डाला। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गईं, जहां उन्हें भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने 15,113 वोटों के अंतर से पराजित किया। इस हार को राज्य की राजनीति में एक बड़े युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। परिणाम के बाद उनके समर्थकों में निराशा और विपक्षी खेमे में उत्साह का माहौल देखा गया। इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को भी बहरामपुर सीट पर हार का सामना करना पड़ा। भाजपा उम्मीदवार शुभ्रत मैत्रा ने उन्हें 17,548 वोटों के अंतर से हराकर एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। यह परिणाम कांग्रेस के लिए राज्य में और भी कमजोर स्थिति का संकेत माना जा रहा है।

चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। ममता बनर्जी ने इसे "लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लूट" करार दिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सीटों पर अनियमितताएं हुईं और केंद्र सरकार के प्रभाव के कारण चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हुई। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी भविष्य में वापसी करेगी और संघर्ष जारी रहेगा। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को जनता की शक्ति और सुशासन की राजनीति की जीत बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास और परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है। वहीं अमित शाह ने भी जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह परिणाम भय, तुष्टीकरण और घुसपैठ जैसे मुद्दों के खिलाफ जनादेश है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य ने पश्चिम बंगाल को एक नए राजनीतिक अध्याय में प्रवेश करवा दिया है। वर्षों से चले आ रहे सत्ता संतुलन के टूटने के बाद अब राज्य में प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। समर्थकों का मानना है कि यह जीत विकास और स्थिरता की नई शुरुआत है, जबकि आलोचकों का कहना है कि आगे की राह चुनौतीपूर्ण होगी और नई सरकार को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक पुनर्संरचना का संकेत है। जहां एक ओर भाजपा ने अपने संगठन और रणनीति के दम पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वहीं विपक्ष के सामने अब खुद को पुनर्गठित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अंततः, पश्चिम बंगाल का यह चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर बनकर सामने आया है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में परिवर्तन हमेशा संभव है और जनता का निर्णय ही अंतिम शक्ति होता है।

आधार कार्ड व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, विधायी सुधार की ओर संकेत

नई दिल्ली। देश की पहचान प्रणाली से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल आधार कार्ड को लेकर एक बार फिर कानूनी और नीतिगत बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट संकेत दिया कि केवल न्यायिक आदेशों से नहीं, बल्कि विधायी हस्तक्षेप और मौजूदा कानूनी ढांचे में संशोधन के माध्यम से ही इस व्यवस्था से जुड़े जटिल प्रश्नों का समाधान संभव है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि केवल छह वर्ष तक की आयु के नागरिकों को ही नया आधार कार्ड जारी किया जाए और उसके बाद के मामलों में सख्त नियंत्रण प्रणाली लागू की जाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इससे पहचान से जुड़ी संभावित धोखाधड़ी और अवैध प्रवास पर रोक लगाई जा सकती है।

हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह के नीतिगत निर्णय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और इनके लिए व्यापक विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अदालत ने कहा कि इस प्रकार के मुद्दों पर केवल न्यायिक निर्देश पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इन्हें सरकार और

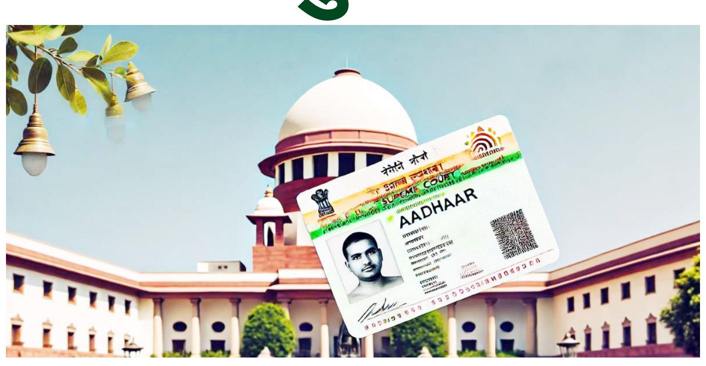

संबंधित हितधारकों के समक्ष उठाया जाना चाहिए ताकि एक संतुलित और व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके।

पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के लिए उचित मार्ग यह होगा कि वह अपने सुझावों और चिंताओं को सरकार तथा अन्य संबंधित संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत करे, जहां इस पर विस्तार से विचार किया जा सके। अदालत ने इसी आधार पर याचिका का निपटारा करते हुए इसे अभ्यावेदन के रूप में मानने का निर्देश दिया। यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सख्त और नियंत्रित बनाने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि किशोरों और वयस्कों के लिए आधार जारी करने की प्रक्रिया में कड़े दिशानिर्देश होने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की पहचान संबंधी धोखाधड़ी या फर्जी नागरिकता के मामलों को रोका जा सके। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी सामने आया कि भारत जैसे विशाल और जनसंख्या वाले देश में पहचान प्रणाली को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। आधार प्रणाली का उपयोग बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, शिक्षा, कर प्रणाली और कई अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि ऐसे मामलों में नीति निर्धारण केवल न्यायिक हस्तक्षेप से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए संसद और सरकार की भूमिका निर्णायक होती है। अदालत का यह दृष्टिकोण इस बात को भी रेखांकित करता है कि जटिल सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों का समाधान बहु-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। आधार प्रणाली को लेकर पहले भी कई बार विभिन्न स्तरों पर बहस होती रही है, जिसमें गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और उपयोग की सीमाओं जैसे मुद्दे शामिल रहे हैं। इस ताजा मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मौजूदा ढांचा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम है या इसमें समय-समय पर सुधार की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल एक याचिका के निपटारे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक संकेत है कि डिजिटल पहचान प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेते समय कानूनी, तकनीकी और नीतिगत सभी पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है और क्या आधार प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए कोई नया विधायी ढांचा तैयार किया जाता है।

बंगाल में चुनावी परिणाम के बाद उत्सव राजनीतिक बदलाव की नई लहर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार का चुनाव परिणाम एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मिली कथित प्रचंड जीत के बाद पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल देखने को मिला। राजधानी कोलकाता से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पार्टी समर्थकों ने जश्न मनाया और राजनीतिक परिदृश्य में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया।

कोलकाता स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने बांग्ला गीतों की धुन पर नाचते-गाते हुए जीत का स्वागत किया। माहौल पूरी तरह उत्साह और उमंग से भरा हुआ था। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई, विशेष रूप से झालमुरी और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। यह दृश्य केवल एक चुनावी जीत का नहीं, बल्कि एक भावनात्मक राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक बन गया।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक-दूसरे पर गुलाल और फूल बरसाकर अपनी खुशी व्यक्त की। कई स्थानों पर लोग भाजपा का झंडा लहराते हुए सड़कों पर उतर आए। समर्थकों का कहना था कि यह जीत वर्षों की मेहनत, संघर्ष और संगठनात्मक प्रयासों का परिणाम है। उनके अनुसार, अब

राज्य में विकास की नई शुरुआत होगी और लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक असंतुलन में बदलाव आएगा।

इस पूरे माहौल में एक विशेष राजनीतिक भावनात्मकता भी देखने को मिली, जिसमें कई समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल, जिसे कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा की भूमि माना जाता है, अब एक नए राजनीतिक युग में प्रवेश कर रहा है। इस संदर्भ में कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि विचारधारा के विस्तार का भी संकेत है।

राज्य के कई हिस्सों में "जय श्री राम" के नारों की गूंज सुनाई दी। जैसे ही चुनावी रुझान भाजपा के पक्ष में आते दिखाई दिए, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उत्साहपूर्वक नारेबाजी करने लगे। प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेकर जुलूस निकाले गए और मिठाइयां बांटी गईं। यह दृश्य राजनीतिक उत्साह और जनसमर्थन के प्रदर्शन के रूप में देखा गया।

24 परगना जिले के काकद्वीप जैसे क्षेत्रों में भी उत्सव का माहौल देखने को मिला, जहां लोग नाचते-गाते हुए "ईबार भाजपा सरकार" के नारे लगा रहे थे। इस नारे ने पूरे क्षेत्र में राजनीतिक बदलाव की उम्मीदों को और अधिक प्रबल कर दिया। समर्थकों का कहना था कि वे परिवर्तन चाहते हैं और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे चुनावी परिणाम केवल जीत या हार तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां दशकों से एक विशेष राजनीतिक धारा का प्रभाव रहा है, वहां इस प्रकार का बदलाव राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है।

हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि इस तरह के उत्सव और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अक्सर चुनावी माहौल की तात्कालिक भावनाओं को दर्शाती हैं। वास्तविक प्रशासनिक बदलाव और विकास की प्रक्रिया समय के साथ ही स्पष्ट हो पाती है। इसलिए, आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि नई राजनीतिक व्यवस्था जनता की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है।

राज्य में इस कथित जीत के बाद राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों की ओर से इस परिणाम पर गंभीर मंथन किया जा रहा है, जबकि भाजपा समर्थक इसे ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। यह स्थिति आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक नई दिशा दे सकती है।

अंततः, यह पूरा घटनाक्रम केवल एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि जनभावनाओं, राजनीतिक विचारधाराओं और भविष्य की अपेक्षाओं का संगम प्रतीत होता है। बंगाल की धरती पर इस तरह का उत्सव यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में हर चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज की सोच और दिशा में संभावित बदलाव का संकेत भी होता है।

उपचुनावों में भाजपा का दबदबा, कई राज्यों में मजबूत हुई राजनीतिक पकड़

नई दिल्ली। देश के विभिन्न राज्यों में हुए ताजा उपचुनावों ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दलों की जमीन पर पकड़ को स्पष्ट कर दिया है। सात विधानसभा सीटों पर हुए इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने चार सीटों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा, जबकि कांग्रेस ने दो सीटों पर सफलता हासिल की और एक सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में गई। इन परिणामों ने यह संकेत दिया है कि राज्यों में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच मुकाबला अभी भी बेहद दिलचस्प और प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। इन उपचुनावों का आयोजन गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नगालैंड और त्रिपुरा जैसे पांच राज्यों में हुआ था। हर राज्य के परिणाम अपने-अपने राजनीतिक समीकरणों और स्थानीय मुद्दों को दर्शाते हैं, लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो भाजपा ने अपने संगठन और रणनीति के बल पर बढ़त बनाए रखी है। खासकर उन राज्यों में जहां पार्टी पहले से मजबूत स्थिति में थी, वहां उसने अपनी पकड़ को और मजबूत किया है।

गुजरात की उमरेठ विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार हर्षद परमार ने कांग्रेस के भृगुराजसिंह चौहान को 30 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। यह जीत न केवल भाजपा के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि राज्य में उसकी पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। इसी तरह नगालैंड के कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र में

भाजपा उम्मीदवार दाओचिर आई इम्चेन ने 3,123 मतों के अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने कुल 7,317 वोट प्राप्त किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार को 4,194 वोट मिले।

त्रिपुरा की धर्मनगर सीट पर भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां पार्टी के उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती ने 18,290 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही त्रिपुरा विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जो राज्य में पार्टी की मजबूत स्थिति को दर्शाती है। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार अक्षय करदिले ने विपक्षी उम्मीदवार को 1.12 लाख से अधिक मतों के बड़े अंतर से हराया, जो इस उपचुनाव की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जा रही है।

महाराष्ट्र में ही बारामती सीट पर सुनेत्रा अजित पवार ने जीत हासिल की, जिससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। यह परिणाम राज्य की जटिल राजनीतिक स्थिति और गठबंधन की राजनीति को भी दर्शाता है, जहां हर सीट का महत्व काफी बढ़ जाता है।

दूसरी ओर, कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। बागलकोट विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उमेश मेती ने 22,332 मतों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं दावणगेरे दक्षिण सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ मल्लिकार्जुन ने भाजपा प्रत्याशी को हराकर पार्टी को मजबूती दी। यह परिणाम दर्शाता है कि कर्नाटक में कांग्रेस अभी भी मजबूत स्थिति में है और सत्तारूढ़ दल होने का लाभ उसे मिल रहा है।

इन उपचुनावों के नतीजे यह स्पष्ट करते हैं कि देश की राजनीति में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच संतुलन बना हुआ है, लेकिन भाजपा लगातार अपने विस्तार और पकड़ को मजबूत कर रही है। जहां एक ओर भाजपा ने चार सीटों पर जीत हासिल कर बढ़त बनाई, वहीं कांग्रेस और अन्य दलों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनावों के परिणाम अक्सर स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और संगठन की सक्रियता पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये परिणाम आने वाले बड़े चुनावों के लिए संकेत भी देते हैं। भाजपा की इन जीतों को उसके मजबूत संगठन, बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ताओं और प्रभावी चुनावी रणनीति का परिणाम माना जा रहा है। इन नतीजों ने यह भी दिखाया है कि भारतीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा लगातार बनी हुई है और कोई भी दल पूरी तरह से अजेय नहीं है। हर राज्य में अलग-अलग समीकरण और चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए दलों को लगातार अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है।

कुल मिलाकर, इन उपचुनावों ने भाजपा को बढ़त जरूर दिलाई है, लेकिन साथ ही विपक्ष के लिए भी यह एक संकेत है कि वह अपनी रणनीति को और मजबूत करे। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये परिणाम राष्ट्रीय राजनीति को किस दिशा में ले जाते हैं और क्या यह रुझान भविष्य के बड़े चुनावों में भी जारी रहता है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

बुजुर्गों के संकट को गंभीरता से ले सरकार

जीवन की सांझ में जब शरीर ढलने लगता है और दिन की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, तब सबसे अधिक आवश्यकता होती है अपनापन, संवाद और सहारे की। लेकिन विडंबना यह है कि आज के बदलते सामाजिक ढांचे में बुजुर्गों के हिस्से में अक्सर अकेलापन, उपेक्षा और भावनात्मक रिक्तता ही आती है। जिन हाथों ने अपने बच्चों को चलना सिखाया, जिन कंधों पर बैठकर बच्चों ने दुनिया देखी, वही हाथ अब सहारे को तरसते हैं और वही कंधे सन्नाटे का भार उठाने को मजबूर हो जाते हैं।

आर्थिक प्रगति, वैश्वीकरण और बेहतर अवसरों की तलाश में नई पीढ़ी का विदेशों या महानगरों की ओर पलायन एक सामान्य प्रवृत्ति बन चुकी है। बच्चों का यह जाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में माता-पिता अक्सर पीछे छूट जाते हैं। बड़े-बड़े घर, जो कभी हंसी-खुशी से गूंजते थे, अब खामोश दीवारों में बदल जाते हैं। दिन भर टीवी की आवाज या खिड़की से बाहर झांकती निगाहें ही उनका साथी बन जाती हैं।

ऐसी परिस्थितियों में "किराये की संतान" जैसी अवधारणाएं उभरकर सामने आई हैं। यह एक नई सामाजिक वास्तविकता है, जहां कंपनियां बुजुर्गों को ऐसे लोगों की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं जो उनके साथ समय बिताते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ खेलते हैं या सैर पर जाते हैं। यह व्यवस्था भले ही अस्थायी राहत देती हो, लेकिन यह उस गहरे भावनात्मक खालीपन को पूरी तरह भर नहीं सकती जो अपने ही बच्चों की अनुपस्थिति से उत्पन्न होता है। फिर भी, जिन बुजुर्गों के पास संसाधन हैं, उनके लिए यह एक तरह से अकेलेपन से लड़ने का साधन बन गया है।

समस्या का दूसरा पक्ष और भी गंभीर है। हर बुजुर्ग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता। खासकर निजी क्षेत्र से सेवानिवृत्त लोगों के लिए जीवन और कठिन हो जाता है। सीमित पेंशन, बढ़ती महंगाई और महंगी चिकित्सा सुविधाएं उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। ऐसे में किराये की सेवाएं लेना उनके लिए संभव नहीं होता। यह स्थिति उन्हें मानसिक तनाव, असुरक्षा और अवसाद की ओर धकेलती है।

विकसित देशों में बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत ढांचा मौजूद है। वहां सरकारें सेवानिवृत्त नागरिकों के स्वास्थ्य, आवास और जीवन-यापन की जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा उठाती हैं। इसके विपरीत, भारत में अभी भी यह व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है। यहां बुजुर्गों को अक्सर अपने ही संसाधनों और परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है। जब परिवार का सहारा कमजोर पड़ता है, तो उनका जीवन और अधिक कठिन हो जाता है।

हालांकि, इस पूरी स्थिति को केवल नकारात्मक दृष्टि से देखना भी उचित नहीं है। यह समय बुजुर्गों के लिए आत्मस्वीकृति और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक अवसर हो सकता है। यदि वे शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने का प्रयास करें, तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार संभव है। योग, प्राणायाम, ध्यान और नियमित दिनचर्या न केवल उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। सत्संग और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी उन्हें एक नई ऊर्जा और उद्देश्य का अनुभव करा सकती है। इसके साथ ही समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गुणवत्तापूर्ण और सुविधा-संपन्न वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, जहां बुजुर्ग केवल रहने की सुविधा ही नहीं, बल्कि सम्मान और अपनापन भी महसूस कर सकें। इसके अलावा, एक अभिनव विचार यह भी सामने आता है कि अनाथ बच्चों और वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों को एक साथ रखा जाए। इससे दोनों की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। बच्चों को जहां स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं बुजुर्गों को अपनेपन का एहसास होगा।

अंततः, यह समझना जरूरी है कि खून के रिश्तों का कोई विकल्प नहीं होता। तकनीक, सेवाएं और व्यवस्थाएं केवल अस्थायी समाधान दे सकती हैं, लेकिन परिवार का स्नेह ही स्थायी संतोष देता है। नई पीढ़ी को भी यह समझना होगा कि जीवन की दौड़ में माता-पिता को पीछे छोड़ देना केवल एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या भी बनता जा रहा है।

जीवन की सांझ को सुंदर और संतोषजनक बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने बुजुर्गों को केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम के साथ देखें। क्योंकि आज जो बुजुर्ग हैं, कल हम भी उसी राह पर होंगे।

दूरगामी नुकसान करा बैठे दक्षिणी राज्य

> "स्वाभाविक है कि दक्षिणी राज्यों को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे वे चाहते तो बच सकते थे। प्रतीत होता है कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ के फेर में वे दूरगामी नुकसान करा बैठे हैं।

बीते दिनों कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल संसदीय परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन की राह में अवरोध पैदा करने में सफल रहे। इस कवायद में कांग्रेस को दक्षिण भारतीय नेताओं का व्यापक रूप से सहयोग मिला। इस घटनाक्रम की गहन पड़ताल करें तो नेताओं का यह रुख दक्षिणी राज्यों के लिए ही भारी भूल साबित हो सकता है। यह विडंबना ही है कि कांग्रेस, द्रमुक और माकपा जैसे दल इस मुद्दे की गहराई और गंभीरता को समझने में विफल रहे और उन्होंने एक बेहतर अवसर गंवा दिया। प्रस्ताव के सकारात्मक पहलुओं से अधिक मोदी सरकार के प्रति नफरत और नकारात्मकता ही उनके इस निर्णय का मुख्य आधार रही।

इस मुद्दे की गहराई में जाएं तो संविधान का अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य को सीटों की आवंटन प्रक्रिया में सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए हरसंभव रूप से व्यावहारिक एवं एकसमान हो। इसी क्रम में अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 'ऐसी प्राधिकारी संस्था द्वारा और ऐसे तरीके से पुनर्गठित किया जाएगा जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे।" इस दृष्टि से सरकार और संसद के पास ही यह गुंजाइश है कि वे परिसीमन आयोग की 'व्यावहारिकता' पर विचार करने और केवल जनसंख्या के आंकड़ों पर ही कड़ाई से चलने के बजाय '50 प्रतिशत' से अधिक वाली संकल्पना को आगे बढ़ाने का निर्देश दे सकें। सरकार द्वारा लोकसभा सीटों में 'एकमुश्त 50 प्रतिशत' की वृद्धि संबंधी आश्वासनों की गंभीरता का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए था। वर्ष 1971 में परिसीमन न होने के बाद से ही लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग जोर पकड़ती रही। वर्ष

2001 में वाजपेयी सरकार के दौरान भाजपा नेता मदनलाल खुराना ने भी मुखरता से ऐसी मांग सामने रखते हुए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 800 से अधिक करने की बात कही थी। हालांकि चंद्रबाबू नायडू, रामकृष्ण हेगड़े और करुणानिधि जैसे दक्षिण भारतीय नेताओं ने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को लेकर आपत्ति जताई। उनका मानना था कि दक्षिणी राज्यों ने केंद्र सरकार की परिवार नियोजन नीतियों को कहीं बेहतर तरीके से लागू किया था, ऐसे में जनसंख्या के आधार पर होने वाला परिसीमन उन्हें नुकसान पहुंचाता। इसके चलते ही नायडू ने एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री वाजपेयी के पास भेजा और परिसीमन को रोकने की मांग की। वाजपेयी ने इस मांग को स्वीकार किया और अनुच्छेद 81 में संशोधन का निर्णय लिया। इससे लोकसभा की मौजूदा सीटों को 2026 की जनगणना तक स्थिर रखा गया।

इस संदर्भ में दक्षिणी राज्यों की संवेदनाओं को समझते हुए मोदी सरकार ने अनुच्छेद 81 के प्रविधानों को दरकिनार कर परिसीमन संबंधी संवैधानिक संशोधन में एक प्रस्ताव रखा, जिसके तहत सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता तो दक्षिणी राज्यों के लिए लाभ की स्थिति बन सकती थी, लेकिन वहां के अधिकांश राजनीतिक दलों ने इसका अंधविरोध किया। तेलुगु देसम, जन सेना और वाइएसआर कांग्रेस जैसे दलों के समर्थन के बावजूद संविधान संशोधन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। दिलचस्प बात यही है कि यदि यह प्रस्ताव अमल में आता तो शायद उत्तरी राज्यों को जनसंख्या वृद्धि के बाद भी उसका अपेक्षित अनुपातिक लाभ नहीं मिलता। इसके बावजूद उनकी ओर से शिकायत सामने नहीं आई। चूंकि दक्षिणी राज्य इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए शायद उन्हें यह महसूस हो रहा हो कि इसमें उनका कुछ फायदा ही हो।

यदि जनसांख्यिकी परिदृश्य की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए देश की कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर 2.1 होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि एक औसत महिला को अपने जीवनकाल में 2.1 बच्चों को जन्म देना चाहिए। यदि टीएफआर 2.1 से नीचे आए तो जनसंख्या घटने लगती है। भारत में 1970 के दौर से ही उत्तर और मध्य भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों की टीएफआर में स्पष्ट रूप से गिरावट दर्ज हुई थी। वर्ष 2001 के आंकड़े देखें तो भारत की टीएफआर काफी अधिक (3.2) थी, जो 2011 में गिरकर 2.4 रह गई। अब इसके घटकर 2 होने का अनुमान है, जो जनसंख्या स्थिरता की कसौटी के पैमाने से भी कम है। यह निश्चित ही एक उल्लेखनीय सुधार है, क्योंकि ढाई दशक पहले जनसांख्यिकी विशेषज्ञ और नीति-निर्माता ऊंची टीएफआर को लेकर अत्यंत चिंतित थे।

हालांकि इस उपलब्धि के बाद भी कुछ रुझान असंतुलन की ओर संकेत करते हैं। जैसे पिछले दो दशकों में दक्षिण भारतीय राज्यों की टीएफआर में भारी गिरावट आई है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में यह दर ऊंची बनी हुई है। वर्ष 2021 में उत्तरी राज्यों के अनुमानित टीएफआर की बात करें तो यह बिहार में 3, मध्य प्रदेश में 2.6, राजस्थान में 2.4 और उत्तर प्रदेश में 2.7 संभव है। यानी इन राज्यों में अगले कुछ दशकों के दौरान जनसंख्या वृद्धि का रुझान बना रहेगा।

जबकि दक्षिणी राज्यों मे केरल, तमिलनाडु और आंध्र का टीएफआर 1.5 तक गिर चुका है। कर्नाटक और तेलंगाना में यह 1.6 है। इस तरह देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु में 2001 से ही टीएफआर 2.1 से नीचे पहुंच गया, जबकि बड़े उत्तरी राज्यों में यह करीब चार के दायरे में रहा। चूंकि जनगणना की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, इसलिए परिसीमन अब अनुच्छेद 81 और 82 के प्रविधानों के अनुरूप ही होगा।

इसमें जनसंख्या की कसौटी ही मुख्य आधार बनेगी तो उत्तरी राज्यों की सीटों में उससे भी अधिक बढ़ोतरी होगी जो फार्मूला अभी केंद्र सरकार सुझा रही था। स्वाभाविक है कि दक्षिणी राज्यों को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे वे चाहते तो बच सकते थे। प्रतीत होता है कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ के फेर में वे दूरगामी नुकसान करा बैठे हैं।

प्रेरणा

जीवन के सच्चे वर्षों की पहचान

मनुष्य का जीवन केवल समय के प्रवाह का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर क्षण का अपना महत्व और अर्थ होता है। हम अक्सर अपनी उम्र को वर्षों, महीनों और दिनों में मापते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यही हमारे जीवन का सही मापदंड है? यह प्रश्न तब और गहरा हो जाता है जब हम उस कथा को समझते हैं, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अस्सी वर्षों को नकारते हुए स्वयं को मात्र चार वर्ष का बताता है। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक अर्थ को उजागर करने वाला गूढ़ संदेश है।

एक न्यायप्रिय राजा, नौशेरवां, एक दिन अपने राज्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए भेष बदलकर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध किसान दिखाई देता है, जिसकी उम्र स्पष्ट रूप से काफी अधिक लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज और संतोष झलकता है। जब राजा उससे उसकी उम्र पूछते हैं, तो वह मुस्कराकर कहता है—"चार वर्ष।" यह उत्तर सुनकर राजा चकित रह जाते हैं। बार-बार पूछने पर भी वही उत्तर मिलने पर वे स्वयं को प्रकट करते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं।

वृद्ध किसान का उत्तर केवल एक जवाब नहीं, बल्कि जीवन का सार है। वह बताता है कि उसके जीवन के अस्सी वर्ष सांसारिक कार्यों में बीत गए—धन कमाने, परिवार चलाने और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में। ये सभी कार्य आवश्यक हैं, लेकिन वे केवल जीवन को बनाए रखने के साधन हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं। वह कहता है कि इस प्रकार का जीवन तो पशु भी जीते हैं, जहां मुख्य लक्ष्य केवल अस्तित्व को बनाए रखना होता है। मनुष्य को विशेष बनाता है उसका विवेक, उसका आत्मबोध और उसकी आध्यात्मिक चेतना।

वृद्ध के अनुसार, उसके जीवन के "सच्चे वर्ष" वे हैं, जो उसने पिछले चार वर्षों में बिताए हैं। इन वर्षों में उसने ईश्वर-भक्ति, सेवा, दया और सदाचार को अपनाया है। उसने अपने जीवन को केवल अपने तक सीमित न रखकर दूसरों के लिए जीना शुरू किया है। यही वह परिवर्तन है, जो उसके जीवन को वास्तविक अर्थ देता है। यही कारण है कि वह अपने जीवन की गणना उन्हीं चार वर्षों से करता है, क्योंकि वही उसके लिए सार्थक और जीवंत हैं।

यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है कि जीवन की गुणवत्ता उसकी अवधि से अधिक महत्वपूर्ण है। आज के आधुनिक युग में हम अपने जीवन का अधिकांश समय भौतिक उपलब्धियों की दौड़ में बिताते हैं। हम बेहतर नौकरी, अधिक वेतन और उच्च सामाजिक स्थिति की तलाश में लगे रहते हैं। इस प्रक्रिया में हम यह भूल जाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हम अपने भीतर की शांति, संतोष और मानवीय मूल्यों को नजरअंदाज कर देते हैं।

जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तब अक्सर यह एहसास होता है कि हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन वह संतोष और सुकून नहीं पाया, जिसकी हमें तलाश थी। यही वह क्षण होता है, जब हमें समझ में आता है कि सच्चा जीवन क्या होता है। लेकिन यदि यह समझ पहले आ जाए, तो हमारा पूरा जीवन ही बदल सकता है। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि परिवर्तन के लिए कभी देर नहीं होती। चाहे हम जीवन के किसी भी चरण में हों, यदि हम चाहें तो अपनी सोच और अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। हम अपने जीवन में सेवा, करुणा और सदाचार को शामिल कर सकते हैं। यह परिवर्तन न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है।

आज के समय में, जब रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है और लोग आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं, यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर झांकें और यह समझने का प्रयास करें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित है, या उसमें समाज और दूसरों के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है? यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं, तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। लेकिन यदि हम दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं, तो हमारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है।

यह भी जरूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे कार्यों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाएं। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, या बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ अच्छा करना—ये सभी कार्य हमारे जीवन को सच्चा अर्थ देते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम बड़े स्तर पर कुछ करें; छोटे-छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

अंततः, यह समझना आवश्यक है कि जीवन का वास्तविक मूल्य उसकी गहराई में है, न कि उसकी लंबाई में। यदि हम अपने जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित रखते हैं, तो हम उसके वास्तविक आनंद से वंचित रह जाते हैं। लेकिन यदि हम उसमें आध्यात्मिकता, सेवा और प्रेम को शामिल करते हैं, तो हमारा हर दिन एक "सच्चा वर्ष" बन सकता है।

इसलिए, हमें अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है कि हम केवल समय नहीं बिता रहे, बल्कि उसे सार्थक बना रहे हैं। जब हम अपने भीतर संतुलन, शांति और करुणा को विकसित करते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तव में पूर्ण होता है। यही वह संदेश है, जो हमें इस प्रेरणादायक कथा से मिलता है—कि सच्चे जीवन के वर्ष वे हैं, जिनमें हम वास्तव में जीते हैं, न कि केवल समय के साथ चलते हैं।

जिम्मेदारी का मतदान भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसने अपनी सुदृढ़ चुनावी परंपराओं से वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता के बाद से अनेक लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं, जो लोकतांत्रिक मजबूती को दर्शाते हैं। छिटपुट घटनाओं के बावजूद चुनाव प्रक्रिया कभी बाधित नहीं हुई। यह भारतीय मतदाताओं की जागरूकता और लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा को सिद्ध करता है। वोट की ताकत के माध्यम से जनता शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन करती है, चाहे कोई दल लंबे समय से शासन में क्यों न हो।

यह सत्य है कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग की आलोचना समय-समय पर होती रहती है। बैलेट वोटिंग की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद देश की 140 करोड़ जनता का लोकतंत्र में विश्वास अडिग बना रहता है। भारतीय मतदाता अपने मताधिकार की शक्ति को भली-भांति समझते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, जिससे व्यवस्था की मजबूती और निरंतरता सुनिश्चित होती है।

शिक्षा और जागरूकता के विस्तार के साथ दूरदराज के गांवों तक भी लोकतंत्र की शक्ति की समझ पहुंच चुकी है। लोग जानते हैं कि संविधान सर्वोच्च है और उससे ऊपर कुछ नहीं। जब भी उन्हें लगता है कि संशोधन के नाम पर संविधान से छेड़छाड़ हो सकती है, वे अपने मताधिकार से इसका विरोध करते हैं। हाल के चुनावों में भी संविधान के प्रति आस्था प्रमुख मुद्दा रही। वोटिंग मशीनों और मतदाता सूचियों पर विवाद के बावजूद, जब लोकतंत्र की कसौटी पर परख का समय आया, तो करोड़ों मतदाताओं ने भाग लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया। मिथ्या प्रचार और भ्रामक दावों का शोर आम नागरिक रोज सुनता है, लेकिन मतदान के समय उसकी स्वतंत्र सोच सामने आ जाती है। चुनाव परिणाम यह सिद्ध करते हैं कि भारतीय मतदाता सजग है, स्वयं निर्णय लेता है और आसानी से बहकाया नहीं जा सकता। यही परिपक्वता लोकतांत्रिक परम्पराओं की वास्तविक विजय को दर्शाती है।

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुए रिकॉर्ड मतदान ने बताया कि तमाम नकारात्मक प्रचार के बावजूद मतदाताओं ने लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाई। जाति-धर्म के मुद्दे, मतदाता सूचियों पर संदेह और आरोप-प्रत्यारोप के बीच भी जब नागरिक मतदान केंद्रों पर पहुंचे, तो उनके हाथ में सबसे बड़ी शक्ति उनका वोट था। भीषण गर्मी के बावजूद सुबह से लंबी कतारें लगीं, जो जागरूकता और प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। विशेषकर पश्चिम बंगाल में कड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच रिकॉर्ड मतदान ने यह साबित किया कि भारतीय लोकतंत्र परिपक्व है और हर परीक्षा में खरा उतरता है।

यह मतदान विभिन्न मुद्दों—चाहे मतदाता सूची की विश्वसनीयता का प्रश्न हो या क्षेत्रीय अस्मिता—सबका जवाब बनकर सामने आया, क्योंकि भागीदारी अत्यधिक रही। उच्च मतदान के बीच अपेक्षाकृत कम हिंसा लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत है। तमिलनाडु में भी भाषायी और क्षेत्रीय बहसों के बावजूद मतदाताओं ने उत्साह दिखाया। भीषण गर्मी के बावजूद लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग किया। यह दर्शाता है कि मतदाता मुद्दों को समझते हैं और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुआ मतदान देश में सर्वाधिक रहा, जो लोकतांत्रिक जागरूकता का प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण को लेकर बहस के बीच इन चुनावों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही, जो सशक्तीकरण का संकेत देती है। पश्चिम बंगाल, जो कभी छिटपुट हिंसा के लिए चर्चित रहा है, वहां इस बार अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण मतदान हुआ। यह सब दर्शाता है कि भारतीय मतदाता अधिक परिपक्व, जागरूक और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हो चुका है।

चुनाव विशेषज्ञ अक्सर अधिक मतदान के आधार पर सत्ता परिवर्तन का अनुमान लगाते हैं, जबकि कम मतदान को यथास्थिति की स्वीकृति माना जाता है। लेकिन बदलते समय के साथ ये धारणाएं पुनर्विचार की मांग करती हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में रिकॉर्ड मतदान ने यह संकेत दिया है कि मतदाता अब पारंपरिक आकलनों से परे होकर स्वतंत्र निर्णय लेता है। वह अपने मत का संकेत न पहले देता है, न बाद में प्रकट करता है। यही कारण है कि चुनाव पूर्व अनुमान अक्सर गलत साबित होते हैं। भारतीय मतदाता की यह परिपक्वता और जागरूकता लोकतंत्र की वास्तविक ताकत को दर्शाती है।

आज जब दुनिया के कई बड़े देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव और अधिनायकवादी प्रवृत्तियों की चर्चाएं बढ़ रही हैं, भारत अपने विशाल और विविधतापूर्ण ढांचे के साथ लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अत्यधिक गर्मी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद 92.86 प्रतिशत जैसे उच्च मतदान स्तर तक पहुंचना नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी को दर्शाता है। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय मतदाता भ्रामक प्रचार से प्रभावित हुए बिना अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया और जनता की सक्रिय भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता और परिपक्वता को रेखांकित करती है।

अभियान

मां वैष्णो देवी यात्रा: आस्था, तैयारी और आसान दर्शन का संपूर्ण मार्गदर्शन

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ तीर्थ ऐसे हैं, जिनका नाम लेते ही श्रद्धा, समर्पण और ऊर्जा का अद्भुत संगम महसूस होता है। उन्हीं में से एक है वैष्णो देवी मंदिर, जहां हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए कठिनाइयों को पार करते हुए पहुंचते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव की ऐसी यात्रा है, जो व्यक्ति को भीतर से बदल देती है। अगर आप पहली बार इस पवित्र धाम की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सही जानकारी और तैयारी आपके अनुभव को सहज, सुरक्षित और यादगार बना सकती है।

जम्मू-कश्मीर के त्रिकूट पर्वत पर स्थित यह पवित्र गुफा मंदिर समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यात्रा का आरंभ कटरा से होता है, जो इस तीर्थ का बेस कैंप माना जाता है। कटरा से माता के भवन तक लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसे श्रद्धालु पैदल, घोड़े, पालकी या अन्य साधनों से पूरा करते हैं। यह चढ़ाई भले ही कठिन लगे, लेकिन रास्ते में मिलने वाली सुविधाएं और "जय माता दी" के जयकारे इसे उत्साह से भर देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कई आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। अब पहाड़ों को काटकर चौड़े और समतल रास्ते बनाए गए हैं, जिससे बुजुर्गों और बच्चों के लिए यात्रा पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गई है। पूरे मार्ग में जगह-जगह विश्राम स्थल, पेयजल, शौचालय और शाकाहारी भोजन की व्यवस्था उपलब्ध रहती है, जो 24 घंटे संचालित होती है। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, जिससे श्रद्धालु निश्चिंत होकर यात्रा कर सकें।

अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते, तो आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं। कटरा से भवन तक पिट्ठू, घोड़े और पालकी की सेवाएं आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा हेलिकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो कटरा से सांझी छत तक ले जाती है। सांझी छत से भवन की दूरी मात्र ढाई किलोमीटर रह जाती है, जिसे आसानी से पैदल पूरा किया जा सकता है। यह विकल्प खासकर उन लोगों के लिए लाभदायक है, जो समय या स्वास्थ्य कारणों से पूरी चढ़ाई नहीं कर सकते।

यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सही समय का चयन। वैसे तो यह धाम पूरे वर्ष खुला रहता है, लेकिन हर मौसम का अपना अलग अनुभव होता है। गर्मियों में मई और जून के दौरान यहां भारी भीड़ होती है, क्योंकि यह छुट्टियों का समय होता है। नवरात्रि के दौरान भी यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। अगर आप शांत और कम भीड़ वाले समय में यात्रा करना चाहते हैं, तो फरवरी से अप्रैल या सितंबर से नवंबर के बीच का समय उपयुक्त माना जाता है। बरसात के मौसम में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान फिसलन और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। वहीं सर्दियों में यहां का तापमान काफी नीचे चला जाता है, इसलिए ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम करना जरूरी होता है।

यात्रा की योजना बनाते समय पहुंचने के साधनों की जानकारी भी जरूरी है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं, तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू में स्थित है, जहां से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से टैक्सी या बस के माध्यम से आसानी से कटरा पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन सबसे सुविधाजनक विकल्प है, जो देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से भी जम्मू और कटरा अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, जिससे बस या निजी वाहन से यात्रा करना आसान हो जाता है।

यात्रा के दौरान सही सामान साथ रखना भी बेहद जरूरी है। चूंकि कटरा और भवन के बीच ऊंचाई में काफी अंतर है, इसलिए तापमान में भी बदलाव महसूस होता है। गर्मियों में हल्के कपड़े पर्याप्त होते हैं, लेकिन रात के समय हल्की ठंड से बचने के लिए एक जैकेट साथ रखना अच्छा रहता है। सर्दियों में ऊनी कपड़े, दस्ताने और टोपी जरूरी होते हैं। बरसात के मौसम में छाता या रेनकोट अवश्य रखें। सबसे महत्वपूर्ण है आरामदायक जूते पहनना, क्योंकि पूरी यात्रा में पैदल चलना पड़ता है और सही जूते आपके अनुभव को काफी आसान बना सकते हैं। यात्रा से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना भी आवश्यक होता है, जिसे यात्रा पर्ची कहा जाता है। यह पर्ची कटरा पहुंचने के बाद भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भीड़ के समय पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना बेहतर होता है। इससे आपको यात्रा में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा मोबाइल, पहचान पत्र और जरूरी दवाइयों को साथ रखना न भूलें।

इस यात्रा का सबसे खास पहलू केवल गंतव्य नहीं, बल्कि पूरा सफर होता है। रास्ते में मिलने वाले लोग, उनकी आस्था, उनके चेहरे पर झलकती उम्मीद और ऊर्जा—ये सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो मन को सकारात्मकता से भर देता है। जब आप कठिन चढ़ाई के बाद माता के दरबार में पहुंचते हैं, तो वह क्षण जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान, सारी परेशानियां एक पल में समाप्त हो गई हों। आधुनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं ने इस यात्रा को पहले से कहीं अधिक सरल और सुरक्षित बना दिया है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक महत्ता आज भी उतनी ही गहरी है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि विश्वास और धैर्य के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह केवल माता के दर्शन की यात्रा नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे अनुभव करने का अवसर भी है।

अंततः, अगर आप वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो इसे केवल एक पर्यटन यात्रा न समझें। इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखें, जहां हर कदम आपको अपने भीतर के और करीब ले जाता है। सही योजना, उचित तैयारी और सच्ची श्रद्धा के साथ की गई यह यात्रा निश्चित ही आपके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक बन जाएगी। "जय माता दी" के जयकारों के बीच जब आप इस पवित्र धाम तक पहुंचेंगे, तो आपको महसूस होगा कि यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य आह्वान था, जिसका उत्तर आपने पूरे मन से दिया।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक पटकथा: 'स्टार' से 'सत्ता' तक विजय का ब्लॉकबस्टर डेब्यू, द्रविड़ राजनीति की जकड़न टूटी

चेन्नई। दक्षिण भारत की राजनीति में दशकों से चली आ रही सत्ता की परंपरा को इस बार एक ऐसे चेहरे ने तोड़ दिया, जिसकी पहचान अब तक पर्दे पर थी, लेकिन जनता ने उसे सत्ता के मंच पर भी उतनी ही मजबूती से स्वीकार कर लिया। तमिलनाडु की राजनीति में 60 वर्षों से चला आ रहा द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच सत्ता परिवर्तन का चक्र इस बार पूरी तरह बदल गया है। अभिनेता से नेता बने विजय ने अपनी पार्टी तमिलागा वेत्री कषगम के साथ ऐसा राजनीतिक धमाका किया है, जिसने न केवल राज्य की सत्ता समीकरण बदल दिए हैं बल्कि पूरे देश में एक नए राजनीतिक प्रयोग की चर्चा को जन्म दे दिया है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी टीवीके ने 107 सीटों पर जीत दर्ज कर खुद को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया है। यह आंकड़ा केवल एक जीत नहीं, बल्कि उस जनभावना का प्रतीक है जो वर्षों से एक वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश में थी। द्रमुक और अन्नाद्रमुक जैसे मजबूत दलों के बीच तीसरी शक्ति के रूप में उभरना ही अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन सीधे शीर्ष पर पहुंच जाना राजनीति के पारंपरिक समीकरणों को चुनौती देने जैसा है। चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता अब केवल पुराने ढांचे में बंधकर राजनीति नहीं करना चाहती। टीवीके की 107 सीटों की जीत के मुकाबले AIADMK गठबंधन 53 सीटों पर सिमट गया, जबकि DMK और उसके सहयोगियों को महज 66 सीटों पर संतोष करना पड़ा। यह नतीजे इस बात के संकेत हैं कि राज्य की राजनीति में गहरी परिवर्तन की लहर चल रही है, जिसने दशकों से जमी जड़ों को हिला दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय की लोकप्रियता केवल उनके फिल्मी करियर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अपनी छवि को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो युवाओं, मध्यम वर्ग और बदलाव चाहने वाले मतदाताओं की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता है। उनके भाषणों में सादगी, मुद्दों पर स्पष्टता और जनता से सीधा संवाद उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग बनाता है। यही कारण रहा कि पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। मतगणना के दिन से ही राज्यभर में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिला। जैसे-जैसे टीवीके के पक्ष में रुझान आते गए, समर्थकों में जोश बढ़ता गया। पार्टी का चुनाव चिन्ह 'सीटी' इस बार जश्न का प्रतीक बन गया। जगह-जगह कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सीटी बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। चेन्नई से लेकर छोटे कस्बों तक सड़कों पर जश्न का माहौल रहा, जहां लोगों ने नृत्य किया, मिठाइयां बांटी और अपने नए नेता के समर्थन में नारे लगाए। यह जीत केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी रही। जब परिणाम स्पष्ट होने लगे तो विजय के परिवार में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। उनके माता-पिता टेलीविजन के सामने बैठकर मतगणना देख रहे थे और जैसे ही पार्टी की बढ़त पक्की होती गई, उनके चेहरों पर संतोष और गर्व की झलक साफ दिखाई दी। यह एक ऐसे परिवार की भावना थी जिसने अपने बेटे को फिल्मी दुनिया से राजनीति के कठिन मैदान तक पहुंचते देखा और अब उसे सफलता की ऊंचाई पर खड़ा पाया। जीत पक्की होने के बाद जब विजय अपने समर्थकों का आभार जताने निकले तो पूरा माहौल किसी फिल्मी दृश्य जैसा प्रतीत हो रहा था। उनकी कार पर फूलों की बारिश की गई, सड़कों पर हजारों समर्थक उमड़ पड़े और हर तरफ 'विजय' के नारे गूंजने लगे। यह दृश्य केवल एक नेता की जीत का नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत का संकेत था। दूसरी ओर, इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका एम.के. स्टालिन और उनकी पार्टी DMK को लगा है। मुख्यमंत्री रहते हुए हार का सामना करना और सत्ता से बाहर होना उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। हालांकि, उन्होंने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी लोकतंत्र की भावना का सम्मान करती है और अब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उनका यह बयान इस बात का संकेत है कि द्रमुक अब नई रणनीति के साथ वापसी की कोशिश करेगा। इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अन्नाद्रमुक, जो कभी राज्य की राजनीति का मजबूत स्तंभ मानी जाती थी, अब तीसरे स्थान पर खिसक गई है। AIADMK की यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि राज्य की राजनीति में पुराने समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और मतदाता अब नए विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं।

राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी यह परिणाम बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विजय की सफलता उन राष्ट्रीय दलों के लिए भी एक संकेत है, जो अब तक तमिलनाडु में अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना सके थे। यह चुनाव यह साबित करता है कि यदि कोई नया नेतृत्व जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाता है और भरोसा जीतता है, तो वह स्थापित राजनीतिक ढांचे को भी चुनौती दे सकता है।

तमिलनाडु की राजनीति में यह बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक मानसिक बदलाव का भी संकेत है। यह चुनाव दर्शाता है कि जनता अब केवल परंपरागत राजनीति से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो नए विचार, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आए। विजय की जीत इसी बदलाव का प्रतीक बनकर उभरी है। आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या तमिलागा वेत्री कषगम इस जनादेश को स्थायी समर्थन में बदल पाएगी और क्या विजय अपनी लोकप्रियता को प्रभावी शासन में तब्दील कर पाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें 'स्टार पावर' और 'जन समर्थन' का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, और यह कहानी आगे किस दिशा में जाएगी, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।

अपने संसाधनों से विकास की नई पटकथा: बिना कर्ज गढ़ा गया गंगा एक्सप्रेस-वे बना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पहचान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है, जिसने न केवल राज्य की आर्थिक सोच को बदला है बल्कि पूरे देश के लिए एक नया मॉडल भी प्रस्तुत किया है। करीब 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे अब सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, वित्तीय अनुशासन और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक बनकर उभरा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसे बिना किसी बैंक कर्ज के पूरा किया गया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को राज्य की आर्थिक क्षमता और प्रशासनिक इच्छाशक्ति का उदाहरण बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब उन राज्यों की श्रेणी में आ चुका है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अपने संसाधनों के बल पर पूरा करने में सक्षम हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे पर लगभग 36,000 करोड़ रुपये की लागत आई, जबकि इसके साथ विकसित किए जा रहे इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब को मिलाकर कुल परियोजना लागत 42,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

यह एक्सप्रेस-वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी हिस्सों से जोड़ते हुए राज्य की आर्थिक धुरी को मजबूत करेगा। मेरठ से प्रयागराज तक फैला यह मार्ग न केवल यात्रा समय को कम करेगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और निवेश के नए अवसर भी खोलेगा। एक्सप्रेस-वे के किनारे विकसित किए जा रहे नौ इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब इस परियोजना को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इन हब्स के लिए करीब 7,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है, जहां भविष्य में बड़े उद्योग, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक सेवाओं का नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

इस पूरी योजना का मूल उद्देश्य सिर्फ सड़क निर्माण नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक इकोसिस्टम तैयार करना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स राज्य को 'ट्रांजिट इकोनॉमी' से 'प्रोडक्टिव इकोनॉमी' की ओर ले जाते हैं, जहां सिर्फ आवागमन ही नहीं, बल्कि उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया भी तेज होती है।

मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि 2017 से पहले की स्थिति बिल्कुल अलग थी, जब राज्य को "बीमारू" कहा जाता था और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बैंकों से कर्ज लेना भी मुश्किल होता था। उस समय वित्तीय कुप्रबंधन और संसाधनों के दुरुपयोग के कारण राज्य की साख कमजोर हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के कारण उत्तर प्रदेश ने अपनी छवि बदलते हुए खुद को "रेवेन्यू सरप्लस स्टेट" के रूप में स्थापित किया है। इस बदलाव का असर राज्य की आय, बजट और प्रति व्यक्ति आय में भी साफ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन तीनों क्षेत्रों में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य की आर्थिक मजबूती का संकेत है। एक्साइज राजस्व का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यह 12,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 62-63 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह वृद्धि केवल करों में बढ़ोतरी से नहीं, बल्कि लीकेज रोकने और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण संभव हो पाई है।

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इससे जुड़े विकास कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और समयबद्ध तरीके से काम पूरा हो। यही कारण है कि यह परियोजना बिना किसी बड़े विवाद या देरी के तेजी से आगे बढ़ी और अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 500 नए लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इनमें 371 सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षक तथा 129 स्थानीय निधि लेखा परीक्षक शामिल हैं। यह कदम राज्य की वित्तीय निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जो लंबे समय में विकास को स्थायी बनाने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में लखनऊ के जेपीएनआईसी प्रोजेक्ट का उदाहरण देते हुए पिछली सरकारों के वित्तीय कुप्रबंधन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि यह परियोजना 200 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इसकी लागत बढ़कर 860 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और फिर भी यह अधूरी रह गई। इस तरह की परियोजनाएं न केवल संसाधनों की बर्बादी हैं, बल्कि विकास की गति को भी बाधित करती हैं। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार ने गंगा एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाओं को समय पर और निर्धारित बजट में पूरा करके एक नई कार्यसंस्कृति स्थापित की है। यह कार्यसंस्कृति न केवल सरकारी मशीनरी को अधिक जिम्मेदार बनाती है, बल्कि निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाती है।

बंगाल से दक्षिण तक गूंजा जनादेश का संदेश: नरेंद्र मोदी ने जीत को बताया 'चिरस्मरणीय', कार्यकर्ताओं के संघर्ष और सुशासन पर जताया भरोसा

नई दिल्ली। देश की राजनीति में आए बड़े बदलावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजों को ऐतिहासिक करार देते हुए विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मिली जीत को 'चिरस्मरणीय' बताया है। उन्होंने इसे केवल एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि जनता की शक्ति, विश्वास और सुशासन की राजनीति की विजय बताया। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई संदेशों के माध्यम से न सिर्फ बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया, बल्कि असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति भी सम्मान प्रकट किया।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहा कि यह जनादेश वर्षों के संघर्ष, समर्पण और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने इस जीत को 'कमल के खिलने' के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि यह चुनाव आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। उनके अनुसार, यह नतीजा उस भरोसे का प्रतीक है जो राज्य की जनता ने विकास, पारदर्शिता और सुशासन की राजनीति पर जताया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार बंगाल के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और हर वर्ग को अवसर व सम्मान दिलाने की दिशा में प्रयास करेगी।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेशों में विशेष रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली यह ऐतिहासिक जीत उन अनगिनत कार्यकर्ताओं के वर्षों के संघर्ष के बिना संभव नहीं होती, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी संगठन को मजबूत किया और जनता के बीच पार्टी की नीतियों और विकास के एजेंडे को पहुंचाया। उन्होंने ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र का असली नायक बताते हुए उन्हें नमन किया।

असम में भाजपा और उसके सहयोगियों की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने इसे जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में राज्य में जो प्रगति हुई है, वह केवल सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं के समर्पण का परिणाम है। उनके अनुसार, सकारात्मक राजनीति और विकास के एजेंडे ने ही लोगों के दिलों में जगह बनाई है, जिससे यह जीत संभव हो सकी।

पुडुचेरी के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित किया और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया, वह सराहनीय है। उन्होंने इस जीत को जमीनी स्तर पर किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम बताया और कहा कि जनता ने एक बार फिर राजग पर भरोसा जताया है, जो जिम्मेदारी को और बढ़ाता है।

दक्षिण भारत के अन्य राज्यों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु और केरल के मतदाताओं को भी विशेष संदेश दिया। तमिलनाडु के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो समर्थन भाजपा और राजग को मिला है, वह उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और वे राज्य की जनता की समस्याओं के समाधान तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलागा वेत्री कषगम को भी उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और इसे लोकतंत्र की ताकत का उदाहरण बताया।

केरल के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने वहां भाजपा-राजग को समर्थन देने वाले मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार केरल की प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने में हर संभव सहयोग दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने केरल में जीत दर्ज करने वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को भी बधाई देते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान किया।

प्रधानमंत्री के इन बयानों में एक ओर जहां जीत का उत्साह दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारी का बोध भी स्पष्ट झलकता है। उन्होंने यह संकेत दिया कि यह जनादेश केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उनके अनुसार, सरकार का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर विकास करना और हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री के ये संदेश न केवल चुनावी परिणामों पर प्रतिक्रिया हैं, बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक दिशा का संकेत भी देते हैं। इनमें संगठन की मजबूती, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका और सुशासन के एजेंडे को केंद्र में रखने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है।

कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक आए इन चुनावी नतीजों ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इन जनादेशों को केवल राजनीतिक जीत के रूप में नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं और विश्वास के रूप में देख रही है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन वादों और आश्वासनों को किस तरह जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है और किस प्रकार यह जनादेश देश की राजनीति को नई दिशा देता है।

सूरत में गूंजा जनादेश का स्वर: 'सोनार बांग्ला' से असम तक राष्ट्रवाद और विकास पर मुहर, यह मोदी नेतृत्व पर अटूट विश्वास की जीत-अरविंद सिंह

सूरत। देश के पांच राज्यों में आए विधानसभा चुनाव परिणामों ने जहां राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को नया मोड़ दिया है, वहीं सूरत में भी इस जनादेश की गूंज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। हिंदीभाषी महासंघ के महासचिव, सिवान कबड्डी संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद सिंह ने इन चुनावी नतीजों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे भारतीय राजनीति के एक नए युग की शुरुआत करार दिया। उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक सफलता और असम में लगातार तीसरी बार मिली जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के गहरे विश्वास की अभिव्यक्ति बताया।

अरविंद सिंह ने कहा कि इन चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश की जनता अब केवल वादों पर नहीं, बल्कि ठोस कार्य और दूरदर्शी नेतृत्व पर भरोसा करती है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह देश के आम जनमानस के साथ सीधा संवाद स्थापित किया और उन्हें विकास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रहित के व्यापक विजन से जोड़ा, उसी का परिणाम है कि आज कठिन माने जाने वाले राज्यों में भी भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि बंगाल जैसे राज्य में जहां वर्षों से अलग राजनीतिक धारा प्रभावी रही, वहां इस तरह का जनादेश मिलना परिवर्तन की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीतिक भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि उनकी 'चाणक्य नीति' ने विपक्ष के जटिल राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। अरविंद सिंह के अनुसार, यह जीत केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक भी है, जिसमें राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास जैसे मुद्दों को जनता ने प्राथमिकता दी है।

संगठनात्मक मजबूती पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सफलता का एक बड़ा कारण उसका मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। नितिन नबीन के नेतृत्व में संगठन ने जिस तरह जमीनी स्तर पर कार्य किया, वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया, जिससे पार्टी का संदेश व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंच सका। इस अभियान में मंगल पांडेय की भूमिका को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया और कहा कि उनके प्रभावशाली भाषणों ने लोगों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना को जागृत किया।

असम के संदर्भ में अरविंद सिंह ने कहा कि वहां की जनता ने विकास और स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए एक बार फिर भाजपा-एनडीए को अवसर दिया है। उन्होंने हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में राज्य ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण योजनाओं तक, हर क्षेत्र में हुए बदलावों ने जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है, जिसका परिणाम इस ऐतिहासिक जीत के रूप में सामने आया है।

पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह वहां के कार्यकर्ताओं के सतत प्रयासों और जनता के साथ निरंतर संवाद का परिणाम है। वहीं केरल और तमिलनाडु में बढ़ते जनसमर्थन को उन्होंने भविष्य की राजनीति के लिए सकारात्मक संकेत बताया। उनके अनुसार 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र अब देश के अंतिम छोर कन्याकुमारी तक पहुंच चुका है और यह एक व्यापक राष्ट्रीय भावना का रूप ले चुका है।

इस पूरे चुनावी परिदृश्य में योगी आदित्यनाथ की भूमिका को भी उन्होंने अहम बताया। अरविंद सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की आक्रामक चुनावी रैलियों और उनके सशक्त भाषणों ने देशभर में राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा की। उनके 'जीरो टॉलरेंस' नीति और कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख ने मतदाताओं के मन में सुरक्षा और विश्वास की भावना को मजबूत किया, जिसका असर बंगाल से लेकर असम तक देखने को मिला।

उन्होंने यह भी कहा कि इन चुनाव परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश की जनता अब स्थिर और निर्णायक नेतृत्व चाहती है। लोग ऐसे नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहे हैं जो न केवल विकास की बात करे, बल्कि उसे जमीन पर उतारकर दिखाए। अरविंद सिंह के अनुसार, यह जनादेश केवल एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि एक विचारधारा की जीत है, जिसमें राष्ट्रहित, विकास और सुशासन को केंद्र में रखा गया है। सूरत में इस जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। जगह-जगह मिठाइयां बांटी गईं और लोगों ने एक-दूसरे को बधाई दी। अरविंद सिंह ने इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत उनके समर्पण और मेहनत का परिणाम है और आने वाले समय में भी उन्हें इसी ऊर्जा के साथ जनता के बीच कार्य करना होगा।

कुल मिलाकर, इन चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार किया है। अरविंद सिंह के शब्दों में, यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जनविश्वास की पुनर्स्थापना है, जिसने यह साबित कर दिया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, नीतियां प्रभावी हों और संगठन मजबूत हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता।

सूरत बैंक लूट कांड में बड़ा खुलासा : यूपी से दबोचे गए आरोपी, फर्जी पहचान और हाईटेक प्लानिंग से अंजाम दी थी 50 लाख की वारदात

सूरत। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत के वराछा इलाके में हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की 50 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट ने जहां शहर की कानून-व्यवस्था को झकझोर दिया था, वहीं अब इस मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल लूट कांड में शामिल दो आरोपियों को अयोध्या और गोंडा से गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे पूरे गिरोह के पर्दाफाश की उम्मीद तेज हो गई है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शुभम कुमार अजीत ठाकुर और विकास सिंह अरुण कुमार सिंह के रूप में हुई है। दोनों को ट्रांजिट रिमांड के लिए गोंडा की अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें सूरत लाकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ये दोनों आरोपी लूट की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे और घटना के दौरान मौके पर भी मौजूद थे। जांच में सामने आया है कि इस लूट को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। लूट में इस्तेमाल की गई अपाचे बाइक तेलंगाना से फर्जी आधार कार्ड के जरिए खरीदी गई थी, जिससे उनकी पहचान ट्रेस करना मुश्किल हो सके। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सूरत के रांदेर इलाके में भी फर्जी आईडी के आधार पर किराए का मकान लिया था, जहां वे वारदात से पहले ठहरे हुए थे। घटना को अंजाम देने से ठीक पहले उन्होंने वह मकान खाली कर दिया, जिससे पुलिस को शुरुआती जांच में भ्रमित किया जा सके।

क्राइम ब्रांच की जांच में तकनीकी साक्ष्यों की अहम भूमिका रही। शहर में लगे एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को पहली बड़ी सफलता मिली। 16 अप्रैल को एयरपोर्ट रोड पर संदिग्ध गतिविधियों के कुछ दृश्य कैमरों में कैद हुए थे। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल टावर डेटा और तकनीकी विश्लेषण का सहारा लेते हुए संदिग्ध नंबरों को ट्रैक किया। इसी कड़ी में जांच टीम आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस लूट में पांच से अधिक हथियारबंद बदमाश शामिल थे। सभी ने मिलकर दिनदहाड़े बैंक में प्रवेश किया और कर्मचारियों तथा ग्राहकों को बंधक बना लिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने करीब 50 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान लूट लिया और तीन मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो गए। पूरी वारदात इतनी तेजी से अंजाम दी गई कि मौके पर मौजूद लोग संभल भी नहीं पाए।

इस घटना के बाद बैंक कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। कर्मचारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए 25 और 26 मई को हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। उनका कहना है कि बैंक शाखाओं में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और स्टाफ की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएं।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया है। 120 से अधिक पुलिसकर्मी इस केस को सुलझाने में जुटे हुए हैं। विभिन्न राज्यों में छापेमारी की जा रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा कर लिया जाएगा और लूट की पूरी रकम बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि शहरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत भी है। जिस तरह से अपराधियों ने तकनीक, फर्जी दस्तावेजों और सटीक योजना का इस्तेमाल कर इस लूट को अंजाम दिया, वह यह दर्शाता है कि अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और उससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को भी उतनी ही आधुनिक और सतर्क रणनीति अपनानी होगी। सूरत जैसे व्यस्त और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहर में इस तरह की घटना ने आम नागरिकों और व्यापारिक वर्ग में भी चिंता बढ़ा दी है। लोग अब बैंकिंग सुरक्षा को लेकर अधिक सजग हो गए हैं और प्रशासन से कड़े कदम उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है, जो न केवल इस गिरोह के नेटवर्क को उजागर करेंगे, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण सबक साबित हो सकते हैं।

चुप्पेचाप फूले छाप से 'पोरिबर्तन' तक: शून्य से शिखर तक भाजपा की ऐतिहासिक यात्रा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 का जनादेश केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक लंबे, धैर्यपूर्ण और रणनीतिक संघर्ष का परिणाम बनकर सामने आया है। जिस धरती पर दशकों तक वामपंथ का प्रभाव रहा और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने 200 से अधिक सीटों के साथ पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल कर सत्ता का द्वार खोल दिया है। यह जीत अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे वर्षों की मेहनत, वैचारिक जड़ों की मजबूती और संगठनात्मक विस्तार की एक सतत प्रक्रिया रही है।

इस पूरी कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है जब भाजपा बंगाल की राजनीति में लगभग नगण्य उपस्थिति रखती थी। 1990 के दशक में राज्य की सियासत पूरी तरह वामपंथ के प्रभाव में थी और भाजपा के लिए यहां जमीन बनाना बेहद कठिन कार्य था। ऐसे समय में 1998 का वह चर्चित नारा सामने आया—"चुप्पेचाप फूले छाप"। यह केवल एक चुनावी नारा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की मनोविज्ञान को समझकर तैयार की गई एक रणनीति थी। उस दौर में भाजपा का समर्थन करना खुलकर आसान नहीं था, इसलिए पार्टी ने मतदाताओं से अपील की कि वे बिना शोर-शराबे के, चुपचाप मतदान केंद्र में जाकर कमल के निशान पर मुहर लगाएं। इस रणनीति ने उन लोगों को साहस दिया जो परिवर्तन चाहते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से सामने आने से हिचकते थे।

यही वह दौर था जब भाजपा की वैचारिक नींव को मजबूती मिलनी शुरू हुई। इस नींव के केंद्र में थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी विचारधारा और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने बंगाल में पार्टी के लिए प्रेरणा का काम किया। उनकी जन्मभूमि होने के कारण बंगाल में भाजपा के लिए वैचारिक आधार हमेशा मौजूद रहा, जिसे समय के साथ संगठनात्मक रूप दिया गया।

इस आधार को मजबूत करने में कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तपन सिकदर उन नेताओं में प्रमुख थे, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में संगठन को खड़ा करने का काम किया। जब संसाधन सीमित थे और राजनीतिक माहौल प्रतिकूल, तब उन्होंने गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ा और पार्टी को जमीनी स्तर पर स्थापित किया। उनका काम आज के डोर-टू-डोर कैंपेन का प्रारंभिक स्वरूप माना जा सकता है। इसी तरह सत्यब्रत मुखर्जी ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। वे रणनीति बनाने और कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को पहचानकर उन्हें सही दिशा देने में माहिर थे। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर राजनीति करने पर जोर दिया, जिससे आम जनता के बीच भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ी।

इन नेताओं के प्रयासों ने धीरे-धीरे भाजपा को बंगाल की राजनीति में एक पहचान दिलाई। हालांकि, यह सफर आसान नहीं था। लंबे समय तक पार्टी को सीमित सफलता ही मिलती रही, लेकिन संगठन लगातार मजबूत होता गया। यही संगठन आगे चलकर भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बना।

समय के साथ बंगाल की राजनीति में बदलाव के संकेत मिलने लगे। वामपंथ की पकड़ कमजोर हुई और ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का उदय हुआ। हालांकि, सत्ता परिवर्तन के बावजूद आम जनता की अपेक्षाएं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाईं, जिससे एक नए विकल्प की तलाश शुरू हुई।

भाजपा ने इस अवसर को पहचाना और अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति अपनाई। गांव-गांव तक कार्यकर्ताओं की पहुंच सुनिश्चित की गई और हर स्तर पर संवाद बढ़ाया गया। इसी के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने भी बंगाल को प्राथमिकता दी। नरेंद्र मोदी की रैलियों ने जहां बड़े पैमाने पर जनसमर्थन जुटाया, वहीं अमित शाह की चुनावी रणनीतियों ने संगठन को धार दी।

इसके अलावा भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल जैसे नेताओं ने लो-प्रोफाइल रहकर हाई-इम्पैक्ट रणनीति तैयार की। इन नेताओं ने चुनावी प्रबंधन, बूथ स्तर की तैयारी और संसाधनों के कुशल उपयोग के जरिए पार्टी को मजबूत आधार प्रदान किया।

राज्य स्तर पर सुवेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार और दिलीप घोष जैसे नेताओं ने लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर पार्टी की पकड़ को मजबूत किया। इन नेताओं ने स्थानीय मुद्दों को उठाया और जनता के बीच अपनी सक्रियता बनाए रखी, जिससे भाजपा धीरे-धीरे एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरी।

2026 के चुनाव में इन सभी प्रयासों का परिणाम सामने आया। भाजपा ने न केवल बहुमत का आंकड़ा पार किया, बल्कि 200 से अधिक सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह जीत केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि उस मानसिक बदलाव का संकेत है, जिसमें मतदाताओं ने एक नए विकल्प को स्वीकार किया।

विश्लेषकों का मानना है कि इस जीत के पीछे कई कारक काम कर रहे थे। पहला, मजबूत संगठनात्मक ढांचा, जिसने हर बूथ तक पार्टी की पहुंच सुनिश्चित की। दूसरा, केंद्रीय और राज्य नेतृत्व का प्रभावी समन्वय। तीसरा, मतदाताओं के बीच बदलाव की इच्छा, जिसे भाजपा ने सही तरीके से पहचानकर अपने पक्ष में किया।

"चुप्पेचाप फूले छाप" से शुरू हुआ यह सफर आज "पोरिबर्तन" के रूप में सामने आया है। यह केवल एक नारे का विकास नहीं, बल्कि एक विचार की परिपक्वता है, जिसने वर्षों के संघर्ष के बाद अपना परिणाम दिया।

बंगाल की राजनीति में यह परिवर्तन आने वाले समय में कई नए समीकरणों को जन्म देगा। भाजपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस जनादेश को विकास और सुशासन में बदलने की होगी। वहीं, विपक्ष के लिए यह आत्ममंथन का समय है कि आखिर किन कारणों से वह जनता का विश्वास खो बैठा।

इतिहास के इस मोड़ पर इतना स्पष्ट है कि बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। और इस अध्याय की जड़ें उस दौर में जाकर मिलती हैं, जब कुछ लोग चुपचाप मतदान केंद्रों में जाकर कमल के निशान पर मुहर लगा रहे थे, यह विश्वास करते हुए कि एक दिन यह बीज विशाल वृक्ष बनेगा। आज वही बीज 200 पार के आंकड़े के साथ सत्ता के शिखर पर खड़ा है, और बंगाल की सियासत को एक नई दिशा दे रहा है।

भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत: भावनगर मंडल द्वारा बोटाद एवं जूनागढ़ स्टेशनों पर निःशुल्क शीतल पेयजल वितरण

भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान के मद्देनज़र यात्रियों को राहत प्रदान करने हेतु पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा जनहित में विशेष पहल की गई है। इस क्रम में दिनांक 04 मई, 2026 (सोमवार) को बोटाद एवं जूनागढ़ रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए निःशुल्क शीतल पेयजल वितरण की व्यवस्था की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि बोटाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्षेत्र में यात्रियों—विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों—को ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें भीषण गर्मी से काफी राहत मिली। इस सेवा में सामाजिक कार्यकर्ता श्री चौहान महेशभाई पोपटभाई का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ।

इसी प्रकार जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 एवं प्रतीक्षालय हॉल में यात्रियों के लिए निःशुल्क शीतल पेयजल वितरण किया गया। इस जनहितकारी अभियान में जूनियर चेम्बर इंटरनेशनल (JCI) संस्था का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

दोनों स्टेशनों पर इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने में भावनगर मंडल के वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों, टिकट चेकिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा वितरण कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न किया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा ने कहा, "भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावनगर मंडल द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इस प्रकार की जनहितकारी गतिविधियाँ निरंतर आयोजित की जा रही हैं। यह पहल हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं यात्री-हित के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है।"

भावनगर मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं मानवीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती रहें। भीषण गर्मी के दौरान इस प्रकार की राहत सेवाएँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए केवल 22 दिनों में अहमदाबाद में भारतीय रेलवे ट्रैक पर सभी पांच भारी पोर्टल बीम लॉन्च किए गए

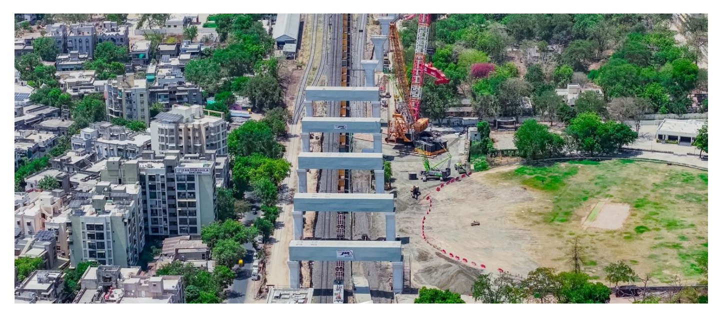

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मणिनगर में अहमदाबाद-वडोदरा रेलवे लाइन के ऊपर, सभी पाँच (05) प्रीकास्ट-प्रीस्ट्रेस्ड भारी पोर्टल बीम (गर्डर) को मात्र 22 दिनों के भीतर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है।

लॉन्चिंग प्रक्रिया 8, 13, 19, 24 और 29 अप्रैल 2026 को पूर्व-नियोजित और चरणबद्ध क्रम में सफलतापूर्वक पूरी की गई। यह कार्य भारतीय रेलवे की सक्रिय पटरियों के ऊपर अत्यंत उच्च स्तर के समन्वय, तीव्र कार्यगति तथा सटीक एवं सुरक्षित निष्पादन के साथ पूरा किया गया। सबसे भारी बीम, जिसका वजन लगभग 1360 एमटी था, 8 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया, जो परिचालन रेलवे लाइनों पर किए गए सबसे भारी लिफ्टों में से एक को चिह्नित करता है। पांचों बीमों में से प्रत्येक का वजन 1170 एमटी से 1360 एमटी के बीच था, जिससे यह रेलवे अवसंरचना पर किए गए सबसे जटिल संरचनात्मक संचालन में से एक बन गया।

मणिनगर में, बुलेट ट्रेन का एलाइनमेंट मौजूदा रेलवे ट्रैकों से ऊँचाई वाले स्तर पर चौंकाने और सीमित ज्यामिति के साथ क्रॉस करती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक संरचनात्मक योजना की आवश्यकता होती है। दो पियर्स के बीच का अंतराल भी अपेक्षाकृत बड़ा है (लगभग 30 मी से 34 मी), जो सुरक्षित रूप से भार स्थानांतरित करने के लिए पोर्टल बीम जैसी मजबूत और कठोर सहायक प्रणाली की आवश्यकता को और बढ़ाता है।

इस स्थान पर पोर्टल बीम को भारी संरचनाओं के रूप में डिज़ाइन किया गया है, ताकि वे भारतीय रेलवे की कई सक्रिय पटरियों—जिनमें अहमदाबाद-वडोदरा की 'अप', 'डाउन' और तीसरी लाइनें शामिल हैं—के ऊपर से गुज़र सकें। इनका विशाल आकार और वज़न इन्हें बेहतर स्थिरता और न्यूनतम नीचे को झुकाव प्रदान करता है, जो इतने व्यस्त रेलवे ट्रैक पर सटीक ट्रैक संरेखण बनाए रखने और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। लॉन्चिंग का काम 2200 मीट्रिक टन क्रॉलर क्रेन का इस्तेमाल करके किया गया, जो मुख्य उपकरण के तौर पर इस्तेमाल हुआ; यह भारत में भारतीय रेलवे ट्रैक पर पहली बार इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक पोर्टल बीम को लगभग 3.5 घंटे में लॉन्च किया गया, जो पहले के 9-घंटे के ब्लॉकों की तुलना में काफी तेज़ है और भारतीय रेलवे के साथ निकट समन्वय में किया गया है। सीमित स्थान, ओएचई (ओवर-हेड इलेक्ट्रिफिकेशन) और सक्रिय रेलवे ट्रैकों जैसी चुनौतियों के बावजूद, संचालन उच्च सटीकता, कड़े सुरक्षा जांच और लगातार निगरानी के साथ पूरा किया गया।

अतिरिक्त जानकारी:

पोर्टल बीम एक प्रीकास्ट कंक्रीट संरचना है, जिसकी लंबाई 34 मीटर है और इसका क्रॉस-सेक्शन 5.5 मीटर गुणा 4.5 मीटर है। इन बीमों को साइट पर ही प्रीकास्ट किया जा रहा है और इन्हें भारी एकीकृत इकाइयों के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

पश्चिम एशिया संकट का असर: एलपीजी खपत में बड़ी गिरावट, ATF और डीजल की रफ्तार भी धीमी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर भारत के ऊर्जा बाजार पर दिखाई देने लगा है। आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं और अंतरराष्ट्रीय मार्गों में अस्थिरता के चलते देश में रसोई गैस यानी एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) की खपत में अप्रैल 2026 के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, एलपीजी खपत 16.16 प्रतिशत घटकर 22 लाख टन रह गई, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 26.2 लाख टन थी। यह गिरावट केवल सालाना आधार पर ही नहीं, बल्कि मासिक स्तर पर भी देखने को मिली है। मार्च 2026 में एलपीजी खपत 23.79 लाख टन थी, जो अप्रैल में और घटकर 22 लाख टन पर आ गई। यह रुझान संकेत देता है कि वैश्विक परिस्थितियों का असर सीधे घरेलू ऊर्जा उपयोग पर पड़ रहा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, और इसका बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए देश तक पहुंचता है। वर्तमान में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। इसी वजह से खाड़ी देशों से आने वाली एलपीजी खेपों में देरी और बाधाएं सामने आई हैं।

आपूर्ति को संतुलित रखने के लिए सरकार ने कुछ तात्कालिक कदम भी उठाए हैं। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं जैसे होटल और उद्योगों को गैस आपूर्ति में कमी की गई है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा सके। साथ ही, घरेलू सिलेंडर की दो रिफिलिंग के बीच अंतराल बढ़ाकर आपूर्ति दबाव को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच, केवल एलपीजी ही नहीं बल्कि अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। विमानन ईंधन, यानी एटीएफ (Aviation Turbine Fuel) की खपत भी 1.37 प्रतिशत घटकर 7.61 लाख टन रह गई है। यह गिरावट संकेत देती है कि हवाई यातायात और ईंधन उपयोग में भी हल्की सुस्ती आई है। इसी तरह डीजल की वृद्धि दर भी लगभग ठहराव पर पहुंच गई है। डीजल की खपत केवल 0.25 प्रतिशत बढ़कर 82.82 लाख टन रही, जो पहले की तुलना में काफी धीमी वृद्धि है। यह स्थिति औद्योगिक गतिविधियों और परिवहन क्षेत्र में सीमित गति को दर्शाती है।

हालांकि पेट्रोल की खपत में 6.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और यह 36.7 लाख टन तक पहुंच गई है, लेकिन यह वृद्धि भी पिछले महीनों की तुलना में धीमी मानी जा रही है। इसका अर्थ है कि भले ही निजी वाहन उपयोग में वृद्धि हो रही हो, लेकिन समग्र ऊर्जा मांग पर दबाव बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के कारण एलपीजी खपत में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी। सरकार की विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी नीतियों के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एलपीजी का उपयोग तेजी से बढ़ा था। लेकिन मौजूदा वैश्विक तनाव ने इस स्थिर वृद्धि की रफ्तार को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है।

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश के लिए अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि आयात पर निर्भरता अधिक होने के कारण वैश्विक आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा सीधे घरेलू कीमतों और उपलब्धता पर असर डालती है। कुल मिलाकर, यह स्थिति स्पष्ट करती है कि ऊर्जा सुरक्षा केवल घरेलू नीतियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्थिरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आने वाले समय में यदि पश्चिम एशिया का तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर केवल एलपीजी ही नहीं, बल्कि पूरे ऊर्जा बाजार पर और अधिक गहराई से देखने को मिल सकता है।

"फाल्गुन फेरी" के उपलक्ष्य में 08 मई को पालीताना से बान्द्रा के लिए चलेगी विशेष ट्रेन, टिकट बुकिंग 5 मई (मंगलवार) से शुरू होगी

यात्रियों की सुविधा तथा "फाल्गुन फेरी" के अवसर पर पालीताना जैन मंदिर में होने वाली क्षद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा विशेष किराये पर पालीताना और बान्द्रा टर्मिनस के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संचालन विवरण:

बान्द्रा टर्मिनस से पालीताना के लिए चलने वाली बान्द्रा-पालीताना सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (09023) दिनांक 06 मई, 2026 (बुधवार) को बान्द्रा टर्मिनस से दोपहर 12.15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन प्रातः 05.10 बजे पालीताना पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में पालीताना-बान्द्रा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (09024) दिनांक 08 मई, 2026 (शुक्रवार) को पालीताना से शाम 17.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 07.25 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सिहोर, सोनगढ़, धोला, बोटाद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी एवं बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपर क्लास एवं एसएलआरडी कोच उपलब्ध रहेंगे।

बुकिंग संबंधी जानकारी :

ट्रेन संख्या 09023 एवं 09024 की बुकिंग दिनांक 05 मई, 20206 (मंगलवार) से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। यात्री ट्रेन के परिचालन समय, ठहराव एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रेलकर्मी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, ट्रैक पर मिला बैग कैश सहित लौटाया

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के गोधरा–वडोदरा रेलखंड पर इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत की-मैन श्री सलीम खान ने अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं मानवता का परिचय देते हुए एक यात्री का खोया हुआ बैग सुरक्षित लौटाकर उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य किया। पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के अंतर्गत वडोदरा-गोधरा सेक्शन पर दिनांक 30 अप्रैल 2026 को ट्रेन संख्या 19165 से वाराणसी जा रहे यात्री श्री दीपक यादव का बैग डेरोल–खरसालिया स्टेशन के मध्य कहीं गिर गया था। सुपरवाइजर द्वारा उन्हें इसे ढूंढने का कार्य दिया गया और अपनी ट्रैक निरीक्षण ड्यूटी के दौरान यह बैग खरसालिया के की-मैन श्री सलीम खान को मिला। बैग की जांच करने पर उसमें लगभग 1,30,000 नकद, मोबाइल फोन, कपड़े एवं अन्य आवश्यक सामान पाया गया। श्री सलीम खान ने पूर्ण ईमानदारी एवं जिम्मेदारी का परिचय देते हुए कैश राशि सहित बैग एवं अन्य बहुमूल्य सामान संबंधित यात्री को सुपरवाइजर के सामने सुरक्षित रूप से उन्हें वापस सौंप दिया।

श्री सलीम खान द्वारा प्रदर्शित यह सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता न केवल रेलवे कर्मचारियों की सकारात्मक कार्यसंस्कृति को दर्शाती है, बल्कि भारतीय रेल के प्रति लोगों के विश्वास को भी और मजबूत करती है।

ऑटो सेक्टर में जोरदार उछाल : बजाज ऑटो की 40% और अशोक लेलैंड की 9% बिक्री वृद्धि से बाजार में नई ऊर्जा

नई दिल्ली। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने अप्रैल 2026 में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू मांग और निर्यात दोनों मोर्चों पर सेक्टर में स्थिर रिकवरी और विस्तार का दौर जारी है। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों में शामिल बजाज ऑटो लिमिटेड और अशोक लेलैंड लिमिटेड ने इस महीने उल्लेखनीय बिक्री वृद्धि दर्ज कर ऑटो बाजार में सकारात्मक रुझान को और मजबूत किया है।

बजाज ऑटो की कुल बिक्री में इस बार 40 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी ने अप्रैल में कुल 5,13,792 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 3,65,810 यूनिट्स था। यह वृद्धि न केवल कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे ऑटो सेक्टर की मजबूती का संकेत भी देती है।

इस प्रदर्शन में सबसे बड़ी भूमिका निर्यात बाजार की रही, जहां बजाज ऑटो ने 83 प्रतिशत की जबरदस्त छलांग लगाई। कंपनी का निर्यात 2,65,582 यूनिट्स तक पहुंच गया। यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय दोपहिया और तिपहिया वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। घरेलू बाजार में भी कंपनी ने स्थिर वृद्धि दर्ज की है। घरेलू बिक्री 13 प्रतिशत बढ़कर 2,48,210 यूनिट्स हो गई। दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री 11 प्रतिशत बढ़कर 2,10,063 यूनिट्स तक पहुंची, जबकि निर्यात में 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ यह आंकड़ा 2,29,890 यूनिट्स तक पहुंच गया।

कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी बजाज ऑटो ने मजबूत प्रदर्शन किया है। इस श्रेणी में 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल 73,839 यूनिट्स की बिक्री हुई। यह संकेत देता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वाणिज्यिक परिवहन की मांग बढ़ रही है।

दूसरी ओर, अशोक लेलैंड लिमिटेड ने भी स्थिर और सकारात्मक प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी की कुल बिक्री 9 प्रतिशत बढ़कर 14,646 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष 13,421 यूनिट्स थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू बाजार की मांग और वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में सुधार के कारण देखने को मिली।

अशोक लेलैंड की घरेलू बिक्री 14 प्रतिशत बढ़कर 14,242 यूनिट्स तक पहुंच गई। कंपनी के मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन (M&HCV) सेगमेंट में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 7,977 यूनिट्स की बिक्री हुई। वहीं हल्के वाणिज्यिक वाहनों (LCV) की बिक्री 6,265 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष 5,103 यूनिट्स थी।

ऑटो सेक्टर के इन ताजा आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय बाजार में मांग लगातार मजबूत हो रही है। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, त्योहारों के बाद की खपत और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में विस्तार ने वाणिज्यिक वाहनों की मांग को बढ़ावा दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात में आई तेजी भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को दर्शाती है। बजाज ऑटो जैसे ब्रांडों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत पकड़ यह संकेत देती है कि भारत अब केवल घरेलू मांग पर निर्भर नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण सप्लायर बन चुका है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों और नए मॉडल्स की बढ़ती मांग भी इस सेक्टर को नई दिशा दे रही है। कंपनियां लगातार तकनीकी नवाचार और नए उत्पाद लॉन्च के जरिए बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं।

कुल मिलाकर, अप्रैल 2026 के ये आंकड़े भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए सकारात्मक संकेत हैं। बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड की वृद्धि यह दिखाती है कि सेक्टर में रिकवरी के साथ-साथ विस्तार का दौर भी जारी है। यदि यही रुझान बना रहता है, तो आने वाले महीनों में ऑटो सेक्टर देश की आर्थिक वृद्धि में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

वडोदरा में प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर की शुरुआत, स्वस्थ वैवाहिक जीवन की दिशा में नई पहल

वडोदरा। महिलाओं के सशक्तिकरण और पारिवारिक जीवन को अधिक संतुलित एवं समझदारीपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सखी वन स्टॉप सेंटर में प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर (PMCC) की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य विवाह से पहले युवाओं को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करना है, ताकि वे वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ सकें और निभा सकें। इस केंद्र के माध्यम से युवा पुरुषों और महिलाओं को संवाद कौशल, आपसी समझ, सम्मान और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। विशेषज्ञ काउंसलिंग सत्रों के जरिए यह प्रयास किया जाएगा कि विवाह से पहले ही संभावित दंपत्ति एक-दूसरे की अपेक्षाओं, सोच और व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सकें, जिससे भविष्य में टकराव की संभावनाएं कम हो सकें।

केंद्र का उद्घाटन सप्लाई ऑफिसर श्रीमती गीताबेन देसाई ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल केवल एक औपचारिक केंद्र नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलते पारिवारिक ढांचे को समझने और उसे मजबूत करने का एक प्रयास है। उनके अनुसार, आज के समय में रिश्तों में संवाद की कमी कई समस्याओं की जड़ बनती जा रही है, जिसे समय रहते समझना बेहद जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह सेंटर दंपत्तियों को केवल वैवाहिक जीवन ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और विवाद समाधान जैसे पहलुओं पर भी प्रशिक्षित करेगा। इससे न केवल व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा, बल्कि परिवारों में भी स्थिरता और संतुलन बढ़ेगा।

यह पहल राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का हिस्सा है, जिसके तहत देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे केंद्र पहले से कार्यरत हैं। अब इसी मॉडल को गुजरात में भी लागू किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर महिलाओं और युवाओं को सीधे लाभ मिल सके।

गुजरात में यह केंद्र महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की पहल से न केवल व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से युवाओं में रिश्तों को लेकर अधिक परिपक्वता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होने की उम्मीद है।

आज के समय में जब विवाह पूर्व और विवाह पश्चात संबंधों में कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं, ऐसे में यह केंद्र एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि युवा पीढ़ी को पहले से ही संवाद और समझदारी के महत्व के बारे में प्रशिक्षित किया जाए, तो भविष्य में कई पारिवारिक विवादों को रोका जा सकता है।

वडोदरा जैसे शहरी और तेजी से विकसित हो रहे शहर में यह पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहां शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ सामाजिक संरचना भी तेजी से बदल रही है। ऐसे में पारिवारिक स्थिरता बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रयास समय की आवश्यकता बन जाते हैं। कुल मिलाकर, प्री-मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर की शुरुआत केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक निवेश है, जो आने वाले समय में मजबूत, समझदार और संतुलित पारिवारिक जीवन की नींव रखने में सहायक हो सकता है।